



भारत के आर्थिक विकास पर डिजिटलाइजेशन का प्रभाव

डॉ. शिवाली शाक्या, सहा. प्राध्यापक (वाणिज्य),

शा. डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)

शोध- सारांश-

वर्तमान युग डिजिटलीकरण का युग है। पिछले कुछ वर्षों में भारत का डिजिटल परिवर्तन उल्लेखनीय रहा है जिसमें स्मार्टफोन, इंटरनेट कनेक्टिविटी व बैंकिंग तकनीक का तीव्र उपयोग डिजिटल अर्थव्यवस्था में तीव्र विकास करने में सफल रहा है। डिजिटलीकरण ने अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक विकास हेतु अवसर प्रदान किए हैं। तेज गति वाले डिजिटलीकरण ने देश की आर्थिक वृद्धि पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। डिजिटलीकरण ने भारत की अर्थव्यवस्था को जिन मुख्य तरीकों से प्रभावित किया है उनमें से एक महत्वपूर्ण कारक ई-कॉमर्स है। ई-कॉमर्स ने भारतीय अर्थव्यवस्था को काफी हद तक प्रभावित किया है। भारत में ई-कॉमर्स की वृद्धि ने व्यवसायों के लिए ग्राहकों तक पहुंच के नए अवसर पैदा किए हैं और उत्पादों और सेवाओं को उपभोक्ता के लिए सुलभ बना दिया है। भारत सरकार भी सक्रिय रूप से डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दे रही है इसके साथ ही वित्तीय क्षेत्रों को भी काफी बढ़ावा मिला है। जैसे-जैसे भारत डिजिटल परिवर्तन के पथ पर आगे बढ़ रहा है वैसे-वैसे वित्तीय क्षेत्र में और अधिक वृद्धि एवं विकास की संभावनाएं नजर आ रही हैं। भारत अपने डिजिटल दशक में है भारत की जीडीपी में डिजिटल अर्थव्यवस्था का अनुमान 2026 तक 20% ज्यादा होने का अनुमान है और भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था 2030 तक 6 गुना बढ़कर 01 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंच सकती है। भारत की इंटरनेट अर्थव्यवस्था मौजूदा दशक के अंत तक अपने जीडीपी के 12-13 प्रतिशत तक बढ़ जाएंगी भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहा है जो डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत करके ही विकसित राष्ट्र के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है।

डिजिटलीकरण ने आर्थिक विकास को तीव्र गति तो प्रदान की है परंतु आज भी कई ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी पर्याप्त न होने के कारण वहाँ के रहवासी तकनीकी साधनों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं एवं तकनीकी साधनों के प्रयोग नहीं कर पाते हैं एवं तकनीकी साधनों के प्रयोग में कई बार धोखाधड़ी एवं जालसाजी होने के कई लोग डिजिटल तकनीक पर भरोसा नहीं कर पाते हैं। भारत के आर्थिक विकास पर डिजिटलीकरण का प्रभाव सकारात्मक रहा है फिर भी देश के सभी नागरिकों को डिजिटल तकनीक के प्रति जागरूक करने की आवश्यकता है जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति डिजिटलीकरण के उपयोग से लाभान्वित हो सके।

Key words - डिजिटलाइजेशन, डिजिटल पेमेंट, ई-गवर्नेंस, ई-कॉमर्स आदि।

शोध परिचय

वर्तमान समय में ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जिसमें डिजिटलाइजेशन की उपयोगिता न हो, चाहे वह शिक्षा जगत हो या मेडिकल फील्ड या विनिर्माण उद्योग या फिर आधुनिक युद्ध तकनीक, सभी क्षेत्रों में डिजिटलाइजेशन महत्वपूर्ण हो गया है। ऐसे में देश के नागरिकों के लिए डिजिटल सशक्तिकरण अब बुनियादी आवश्यकताओं में शामिल हो चुका है। हमारे भारत देश में भी सामान्यतः सभी क्षेत्रों में डिजिटलाइजेशन हो चुका है जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी काफी अधिक प्रभाव पड़ा है। भारत में डिजिटलाइजेशन की शुरुआत 2015 में की गई थी। डिजिटल इंडिया का उद्देश्य भारत को तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बनाना है और भारत में डिजिटल तकनीक से काम करने का चलन अब चरम सीमा पर पहुंच गया है। लोग मोबाइल व इंटरनेट के जरिए उत्पाद या सेवाओं का लाभ ले रहे हैं जैसे:- मोबाइल इंटरनेट के द्वारा सीधे प्रोडक्ट खरीदने के लिए ई-कॉमर्स साइट पर जाना या एप के जरिए प्रोडक्ट ढूंढना व उसे खरीदना, डिजिटल मार्केटिंग की श्रेणी में आता है। आज के समय में ऑनलाइन शॉपिंग, ट्रांजेक्शन, बिल भुगतान, रिचार्ज, टिकट बुकिंग, भुगतान या केश हस्तांतरण आदि बहुत आम हो गया है इससे समय की भी बचत भी होती है क्योंकि व्यक्ति घर बैठे अपने सारे काम आसानी से कर सकता है।

डिजिटल क्षेत्र की कंपनियों के कारोबार में भी प्रतिवर्ष कई प्रतिशत की वृद्धि हुई है साथ ही इस क्षेत्र में लाखों लोगों को ऑनलाइन बिजनेस के माध्यम से रोजगार भी प्राप्त हुआ है। भारत की आर्थिक अर्थव्यवस्था में पूर्व की तुलना में काफी अधिक वृद्धि हुई है जो कि डिजिटलाइजेशन के कारण ही संभव हुई है। डिजिटलाइजेशन ने जहां एक ओर समय की बचत की है वहीं दूसरी ओर पारिवारिक मिलन सारिता को कम कर दिया है अब व्यक्ति मोबाइल पर इंटरनेट व्हाटसअप या विडियो कॉलिंग के माध्यम से अपने रिश्तेदार से बात कर लेते हैं परन्तु एक-दूसरे के घर मिलने नहीं जाते जिससे उनमें आपसी दूरियां बढ़ती हैं।

शोध उद्देश्य-

1. इस शोध अध्ययन का मुख्य उद्देश्य यह जानना है कि डिजिटलाइजेशन का भारत के आर्थिक विकास पर प्रभाव पड़ेगा एवं देश के नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा।
2. द्वितीय उद्देश्य यह जानना कि सरकार द्वारा डिजिटलाइजेशन को भारत में लागू करने से डिजिटल इंडिया के सपने को साकार किया जा सकेगा या नहीं एवं डिजिटलाइजेशन की नवीन विचारधारा किस प्रकार प्रभावी ढंग से कार्य कर सकेगी।

समंक संग्रहण की विधियाँ

इस शोध अध्ययन हेतु समंको को संग्रहण करने के लिए द्वितीयक समंकों को संकलित किया गया है। द्वितीयक समंको के संग्रहण हेतु विभिन्न पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्रों, जर्नल्स, पुस्तकें, शोध पत्र एवं संक्षेपिका एवं इंटरनेट वेबसाइट्स आदि का प्रयोग किया गया है। अतः यह शोध पूर्णतः द्वितीयक समंकों पर आधारित है।

शोध समीक्षा

भारत को अधिक संभावना वाली एक प्रमुख अर्थव्यवस्था बताने वाले **अर्थशास्त्री ए माईकल स्पेन्स** ने कहा है कि देश ने दुनिया की अब तक की सबसे अच्छी डिजिटल अर्थव्यवस्था और वित्तीय ढांचे सफलतापूर्वक विकसित किए हैं। भारत ने दुनिया में अब तक की सबसे अच्छी डिजिटल अर्थव्यवस्था और वित्त वास्तुकला को सफलतापूर्वक विकसित किया है।

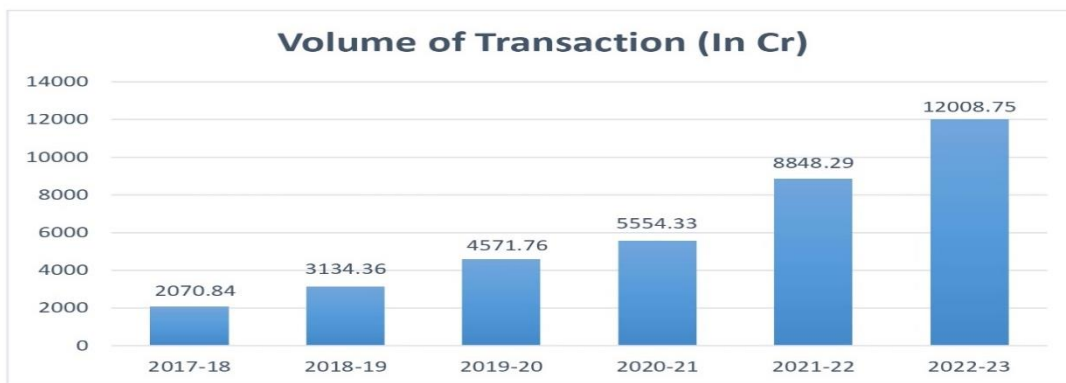
द इकोनॉमी ऑफ ए बिलियन कनेक्टेड रिपोर्ट में कहा गया है कि शहरों में इंटरनेट कनेक्टिविटी का तेजी से विस्तार होना, उपभोक्ता और बिजनेस के लगातार विकास के चलते 2030 तक भारत पूर्णतः डिजिटल भारत बन जाएगा और भविष्य में अधिकांशतः सामान ऑनलाइन ही खरीदा जाएगा।

डिजिटलाइजेशन के इस युग ने संपूर्ण भारत को एक खुला बाजार बना दिया है।

भारत में डिजिटलाइजेशन की आवश्यकता

भारत में डिजिटलाइजेशन लागू करने का अर्थ देश के सभी लोगों तक समस्त सेवाएं डिजिटल रूप में उपलब्ध कराने से है। इससे लोगों को नवीनतम जानकारी और तकनीकी नवाचारों का लाभ मिलेगा। डिजिटलाइजेशन गांवों को समृद्ध करने एवं उनकी उन्नति कराने में लाभदायक सिद्ध होंगे। डिजिटलाइजेशन के माध्यम से डिजिटल लाइव्रीए ऑनलाइन पत्रिकाएँ ई-पुस्तकें मुफ्त में उपलब्ध कराई जा सकती है जो ज्ञान को साझा करने एवं बढ़ाने में मदद करेगी। डिजिटल तकनीक के प्रयोग से गाँवों के लोगों को भी दुनियाभर की समस्त जानकारी इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त होगी एवं उनके शिक्षा के स्तर में भी वृद्धि होगी। 'डिजिटल इंडिया' सिर्फ देश की एक पहल ही नहीं बल्कि इस देश की जरूरत है, जहाँ अभी भी बहुसंख्यक आबादी इन्टरनेट की दुनिया तक नहीं पहुँची है।

डिजिटलाइजेशन का मुख्य उद्देश्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज में बदलना है। भारत में डिजिटलाइजेशन ने भारत के डिजिटल भुगतान के विकास को भी गति दी है। डिजिटलाइजेशन से पहले भारत में सभी लेनदेन में डिजिटल भुगतान का हिस्सा केवल 10 प्रतिशत था लेकिन बाद के वर्षों में यह संख्या 20 प्रतिशत से भी अधिक हो गई है। भारत सरकार डिजिटल इंडिया', मेक इन इंडिया और स्टार्टअप्स जैसी विभिन्न पहलों के माध्यम से डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है। इन पहलों का उद्देश्य स्वास्थ्य, सेवा, शिक्षा व कृषि व्यापार व वाणिज्य आदि क्षेत्रों में डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ाना है जिससे भारत की आर्थिक अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो सके। भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या में काफी वृद्धि हुई है जिसके 2025 तक 9000 मिलियन तक पहुँचने की उम्मीद है। देश में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए UPI, USSD, Adhaar Pay, IMPS, Debit and Credit card भुगतान जैसी डिजिटल भुगतान विधियों का उपयोग उल्लेखनीय रहा है। डिजिटल भुगतान लेनदेन के लिए सरकार का योगदान कैशलेस समाज के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारत में डिजिटल भुगतान में प्रतिवर्ष हो रही वृद्धि को निम्न प्रकार दर्शाया जा सकता है



भारत में डिजिटलाइजेशन के समक्ष चुनौतियाँ

भारत में डिजिटलीकरण का विकास काफी हद तक संभव हो गया है और देश की अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव भी पड़ा है परन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी इंटरनेट और प्रौद्योगिकी की पहुंच सीमित होने के कारण लगभग 40 प्रतिशत आबादी अभी भी ऑफलाइन है। डिजिटल लेनदेन व डेटा शेयरिंग में वृद्धि ने महत्वपूर्ण गोपनीयता और डेटा सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा दिया है। जैसे-जैसे डिजिटलीकरण बढ़ता है साइबर खतरों और हमलों की समस्या भी बढ़ती है। भारत को 2022 में लगभग 91 लाख साइबर सुरक्षा घटनाओं का प्रबंधन सुनिश्चित करना पड़ा है। अतः साइबर सुरक्षा को मजबूत किये जाने की आवश्यकता है। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत आवश्यक साधनों की अपर्याप्तता जैसे- बिजली, ब्राडबैंड नेटवर्क कनेक्टिविटी, बैंकिंग सुविधाओं की कमी आदि कारण डिजिटलाइजेशन लागू करने में बाधक है। इसके अतिरिक्त भारत की ग्रामीण आबादी डिजिटल रूप से अशिक्षित होने के कारण डिजिटल साधनों का प्रयोग करने में असमर्थ है।

डिजिटलाइजेशन को अपनाने हेतु संभावित उपाय

पूर्व आंकड़े बताते हैं कि डिजिटलीकरण में निवेश पूर्व वर्षों की तुलना में काफी अधिक बढ़ा है परंतु निवेश ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ इसकी अत्याधिक आवश्यकता हो अर्थात् ग्रामीण क्षेत्रों में। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति जैसे: बिजली आपूर्ति सस्ती इंटरनेट ब्राडबैंड कनेक्टिविटी, ऑनलाइन सुविधाएं प्रदान करने वाली बैंकिंग सेवाओं की व्यवस्था एवं तकनीकी जागरूकता कार्यक्रम पर व्यय किया जाना चाहिए जिससे ग्रामीण जनता साक्षर हो और इन समस्त तकनीकी सुविधाओं का लाभ उठा सके। डिजिटल भुगतान के समय होने वाली ऑनलाइन धोखाधड़ी से निपटने के लिए साइबर सुरक्षा को मजबूत करना चाहिए। व्यापारिक गतिविधियों के दौरान डिजिटल भुगतान के लिए POS[Point of sale] आदि की उपलब्धता सुनिश्चित की जाना चाहिए। व्यक्तिगत डेटा को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने हेतु 'डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023' को विशेष रूप से लागू कर उपयोग किया जाना चाहिए।

प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। बेहतर परिणामों को प्राप्त करने के लिए इस योजना में और अधिक लक्षित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए जिससे ग्रामीण भारत में काम करने वाले 8.5 लाख स्वास्थ्य कर्मियों और 18 लाख से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को डिजिटल साक्षर बना कर लगभग पूरी ग्रामीण आबादी को डिजिटलीकरण का लाभ प्रदान किया जा सकता है और देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था में सुधार किया जा सकता है।

निष्कर्ष

सामान्यतः डिजिटलाइजेशन की शुरूआत काफी पहले हो चुकी है अब केवल वह विकास की ओर बढ़ रहा है। डिजिटलाइजेशन ने भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में काफी योगदान दिया है परन्तु कुछ चीजें आज भी डिजिटल नहीं होने का कारण उसकी सुरक्षा की कमी है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी इंटरनेट का कार्य तीव्रता से किया जा रहा है जिससे कि ग्रामीण लोगों द्वारा भी तकनीकी लाभ प्राप्त किया जा रहा है। डिजिटलाइजेशन ने भारत की आर्थिक अर्थव्यवस्था को काफी हद तक प्रभावित किया है एवं नागरिकों के जीवन स्तर को भी बढ़ाया है आज अधिकांश व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है और वह मोबाइल के द्वारा अपने बहुत सारे काम करता है। डिजिटलाइजेशन से भारत देश को डिजिटल इंडिया बनाने का सपना जरूर साकार किया जा सकेगा यदि तकनीकी जागरूकता कार्यक्रम को पूर्ण भारत में लागू किया जाए। कई देशों में आईसीटी के उपयोग से आर्थिक विकास दर में वृद्धि को प्रोत्साहित किया है, हमारे देश में भी GDP का प्रतिशत पहले से काफी अधिक बढ़ा है। डिजिटलीकरण के द्वारा डिजिटल भुगतान, ई-गवर्नेंस, ई-कॉमर्स, वित्तीय सामवेशन, ब्रॉडबैंड और इंटरनेट तकनीक को प्रोत्साहित कर आर्थिक विकास पर सकारात्मक प्रभाव डाला है इस विकास को बनाए रखने के लिए और नागरिक कल्याण को बढ़ाने के लिए चुनौतियों का समाधान करना और प्रौद्योगिकी में अधिकाधिक निवेश करना महत्वपूर्ण है साथ ही यह सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण है कि आबादी के सभी वर्गों के लिए डिजिटल अवसर उपलब्ध हों।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- शर्मा, डॉ. रूपलाल शर्मा, अजय कुमार (2021): भारतीय अर्थव्यवस्था के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन पर डिजिटलीकरण का प्रभाव
- श्रीवास्तव, अभिषेक अंजलि (2023) भारत के आर्थिक विकास पर डिजिटलीकरण का प्रभाव
- Shallu, Sihmar Deepikaa (2019): Digitalization In India: An Innovative Concept
- Willson Femandes Jennifer (2018): Digitalization In India: Trends and Challenges.

Important Websites

<https://digipay.gov.in/>

[https://www.India News](https://www.IndiaNews.com)

<https://www.indiabudgeted.gov.in>

<https://www.drishtias.com>

<https://www.linkedin.com>

<https://www.Jagran.com>

[https://www.India TV .com](https://www.IndiaTV.com)

<https://www.eedukemy.com>

Amar Ujala Newspaper